

भी बहुत हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छी है, वहां साड़ी का भी बिजनेस सेंटर है, एल्युमिनियम की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल मिल्स हैं, वहां बहुत डेवलपमेंट है, इसके साथ ही धारवाड़ और हुबली, बेलगांव के नजदीक हैं। यदि इंडियन एयरलाइंस वहां अपने जहाज चलाए और वहां के लोगों को पता चले कि ये रेगुलर चलेंगे तो यह आपके लिए प्रोफिटेबल होगा। आप पंद्रह दिन चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं अगर आप छह महीने चलाएं तो आपके जहाज फुल बुक होंगे। आप वहां चलाकर तो देखिए। इंडियन एयरलाइंस अपने जहाज वहां क्यों नहीं चलाती?

श्री शरद यादव: महोदय, पांच एयरलाइंस ने वहां अपनी सेवाएं दी। ऐसा नहीं कि वहां कोशिश नहीं की। बेलगांव एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, मैं इससे असहमत नहीं हूँ। निश्चित तौर पर जो बड़े जहाज हैं वह वाइबल नहीं हो सकते हैं। छोटे जहाजों का जहां तक सवाल है, मैंने कहा कि लीज पर हम ले लेंगे और जब लीज पर आयेंगे तो बेलगांव जो एक महत्वपूर्ण जगह है, वहां के बारे में निश्चित तौर पर हम देखेंगे और उसकी वाइबिलिटी का फिर से सर्वे करा लेंगे। वाइबिलिटी में ऐसा है कि थोड़ा बहुत, 10, 15 और 20 का अंतर हो सकता है लेकिन वहां वहां पर पांच एयरलाइंस चली हैं और पांचों बंद हो गई हैं।

*223. [The Questioner (Dr. Alladi P. Rajkumar) was absent. For answer vide page 25.....*infra*.]

जल ग्रहण क्षेत्र

*224. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':†

श्री कपिल सिब्बल:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की नदियों के जल को ध्यान में रखते हुए जल ग्रहण क्षेत्रों को तय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में कुल कितने जल ग्रहण क्षेत्रों को तय किया गया है;

(ग) प्रत्येक जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत भूमि और जल की मात्रा कितनी-कितनी है; और

(घ) प्रत्येक जल ग्रहण क्षेत्र में जल संचय की वर्तमान भंडारण क्षमता कितनी-कितनी है?

जल-संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

† सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।

विवरण

(क) से (घ) जी, हां। भारत के जल ग्रहण क्षेत्रों (इन्हें नदी बेसिन भी कहा जाता है) को तीन समूहों में बांटा गया है: (i) 20,000 वर्ग किलोमीटर और उससे अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाले बृहद नदी बेसिन; (ii) 20,000 और 2000 वर्ग किलोमीटर के बीच जल ग्रहण क्षेत्र वाले मध्यम नदी बेसिन और (iii) 2000 वर्ग किलोमीटर से कम जल ग्रहण क्षेत्र वाले लघु नदी बेसिन। देश में कई लघु नदी प्रणालियों के अतिरिक्त 12 बृहद और 46 मध्यम नदी बेसिन हैं। देश में जल संसाधनों की आयोजना और विकास के प्रयोजन के लिए बृहद नदी बेसिनों के अलावा, मध्यम और लघु नदी-प्रणालियों को परस्पर उचित ढंग से मिलाकर आठ संयुक्त (कंपोजिट) बेसिन बनाए गए हैं। सभी 20 बेसिनों के ब्यौरे, उनके जल ग्रहण (भूमि) क्षेत्र और औसत प्रवाह विवरण-'I' में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)। केन्द्रीय जल आयोग के नवीनतम आकलन के अनुसार भारत की नदी-प्रणालियों में औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1869 बिलियन घन मीटर (बी सी एम) है। वर्ष, 1995 तक 177 बी सी एम कुल सक्रिय भंडारण क्षमता मुहैया कराई गई है। निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं वाले बांधों का निर्माण पूरा होने पर 75 बी सी एम अतिरिक्त सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित हो जाएगी। 132 बी सी एम सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए अतिरिक्त बांधों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं/विचाराधीन हैं। प्रत्येक जल ग्रहण क्षेत्र की भंडारण क्षमता विवरण-I में दी गई है।

विवरण-I

भारत में बेसिन-वार भण्डारण (बिलियन क्यूबिक मीटर में)

क्र. सं.	बेसिन नदी का नाम	जल ग्रहण क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	औसत वार्षिक प्रवाह (बीसीएम)	सक्रिय पूरी की गई परियोजनाएं	भण्डारण क्षमता निर्माणाधीन विचाराधीन परियोजनाएं
1	2	3	4	5	6 7
क-प्रमुख नदी बेसिन					
1.	सिंधु	3,21,289	73.31	13.83	2.45 0.27
2.	(क) गंगा	8,61,452	525.02	36.84	17.12 29.56
	(ख) ब्रह्मपुत्र और बराक	2,36,136	585.60	1.09	2.40 63.35
3.	ब्राह्मणी और बैतरणी	51,822	28.48	4.76	0.24 8.72
4.	महानदी	1,41,589	66.88	8.49	5.39 10.96
5.	गोदावरी	3,12,812	110.54	19.51	10.65 8.28
6.	कृष्णा	2,58,948	78.12	34.48	7.78 0.13
7.	पेन्नार	55,213	6.32	0.38	2.13 -
8.	कावेरी	81,155	21.36	7.43	0.39 0.34

1	2	3	4	5	6	7
9.	तापी	65,145	14.88	8.53	1.01	1.99
10.	नर्मदा	98,796	45.64	6.60	16.72	0.47
11.	माही	34,842	11.02	4.75	0.36	0.02
12.	साबरमती	21,674	3.81	1.35	0.12	0.09

ख-संयुक्त (कम्पोजिट) नदी बेसिन

1.	सुवर्णरेखा	29,196	12.37	0.66	1.65	1.59
2.	लुनी सहित कच्छ, सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	3,21,851	15.10	4.31	0.58	3.15
3.	तापी से ताद्री तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	55,940	87.41	7.10	2.66	0.84
4.	ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	56,177	113.53	10.24	2.31	1.70
5.	महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	86,643	22.52	1.63	1.45	0.86
6.	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	1,00,139	16.46	1.42	0.02	-
7.	राजस्थान में अन्तर्देशीय जल निकास क्षेत्र	60,000	नगण्य	0.00	0.00	0.00
8.	बंगलादेश और म्यांमार में गिरने वाली लघु बेसिनें	36,202	31.00	0.31	0.00	0.00
कुल:			1869.35	173.73	75.42	132.32

टिप्पणी :

- केवल 10 मिलियन क्यूबिक मीटर और उससे अधिक की सक्रिय भण्डारण क्षमता वाली परियोजनाएं शामिल हैं।
- 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम क्षमता वाली प्रत्येक मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 3 बिलियन क्यूबिक मीटर (लगभग) अतिरिक्त सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजन कर ली गई है। इस प्रकार पूर्ण परियोजनाओं में कुल सक्रिय भण्डारण क्षमता लगभग 177 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी।
- पूर्णांक करने के कारण योग बराबर नहीं हो सकता है।

[7 August, 2001]

RAJYA SABHA

Water catchment areas

†*224. SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN':††
SHRI KAPIL SIBAL:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that water catchment areas have been marked keeping in view the water of the rivers in the country;
- (b) if so, the total number of water catchment areas marked in the country;
- (c) the area of land and quantum of water under each water catchment area; and
- (d) the present storage capacity of holding water in each catchment area?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI ARJUN CHARAN SETHI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Yes, Sir. The water catchment areas (also called river basins) of India have been classified into the three groups: (i) major river basins having catchment area of 20,000 square kilometre (sqkm) and above; (ii) medium river basins having a catchment area between 20,000 and 2000 sqkm; and (iii) minor river basins having catchment area below 2000 sqkm. There are 12 major and 46 medium river basins besides a number of minor river systems in the country. For the purpose of planning and development of water resources in the country, beside the major river basins, the medium and minor river systems have been suitably combined together into eight composite basins. Details of all the 20 basins their catchment (land) areas, and average flow are given in the Statement-I (*See below*). As per the latest assessment made by the Central Water Commission, the average annual flow in the river systems of India is about 1869 Billion Cubic Metre (BCM). A total live storage capacity of 177 BCM has been provided up to 1995. An additional live storage capacity of 75 BCM will be created on completion of the dams, which are under various stages of construction. Proposals to take up additional dams to create a live storage capacity of 132 BCM are also under formulation/consideration. The storage capacities in each catchment area are also given in Statement-I.

† Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'.

Statement-I

Basin-wise Storage in India (in billion cubic metre)

Sl. No.	Name of the River Basin	Catchment Area (sqkm)	Average Annual Flow (BCM)	Live Storage Capacity		
				Completed Projects	Projects under Construction	Projects under Consideration
1	2	3	4	5	6	7
A	MAJOR RIVER BASINS					
1.	Indus	3,21,289	73.31	13.83	2.45	0.27
2.	(a) Ganges	8,61,452	525.02	36.84	17.12	29.56
	(b) Brahmaputra and Barak	2,36,136	585.60	1.09	2.40	63.35
3.	Brahmani and Baitarni	51,822	28.48	4.76	0.24	8.72
4.	Mahanadi	1,41,589	66.88	8.49	5.39	10.96
5.	Godavari	3,12,812	110.54	19.51	10.65	8.28
6.	Krishna	2,58,948	78.12	34.48	7.78	0.13
7.	Pennar	55,213	6.32	0.38	2.13	—
8.	Cauvery	81,155	21.36	7.43	0.39	0.34
9.	Tapi	65,145	14.88	8.53	1.01	1.99
10.	Narmada	98,796	45.64	6.60	16.72	0.47
11.	Mahi	34,842	11.02	4.75	0.36	0.02
12.	Sabarmati	21,674	3.81	1.35	0.12	0.09
B	COMPOSITE RIVER BASINS					
1.	Subernarekha	29,196	12.37	0.66	1.65	1.59
2.	West flowing rivers of Kutch, Saurashtra including Luni	3,21,851	15.10	4.31	0.58	3.15
3.	West flowing rivers from Tapi to Tadri	55,940	87.41	7.10	2.66	0.84
4.	West flowing rivers from Tadri to Kanyakumari	56,177	113.53	10.24	2.31	1.70
5.	East flowing rivers between Mahanadi and Pennar	86,643	22.52	1.63	1.45	0.86
6.	East flowing rivers between Pennar and Kanyakumari	1,00,139	16.46	1.42	0.02	—
7.	Area of inland drainage in Rajasthan	60,000	Neg.	0.00	0.00	0.00
8.	Minor river basins draining into Bangaldash and Myanmar	36,202	31.00	0.31	0.00	0.00
TOTAL			1869.35	173.73	75.42	132.32

Note: 1. Projects having a live storage capacity of 10 million cubic metre and above only are included.

2. An additional live storage capacity of 3 billion cubic metre (approx.) has been created through Medium. Projects each having a capacity of less than 10 million cubic metre thus making a total live storage capacity of 177 billion cubic metre in completed projects.

3. Totals may not tally due to rounding off.

[7 August, 2001]

RAJYA SABHA

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति महोदय, देश का एक बड़ा भू-भाग जल ग्रहण क्षेत्र से बाहर है और जल ग्रहण क्षेत्र की उचित व्यवस्था के अभाव में वैसे इलाके, जहां अधिक जल है उसके कारण वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और दूसरी तरफ जल ग्रहण क्षेत्र से जो इलाके बाहर हैं, वहां सुखाड़ की स्थिति पैदा होती है, जहां कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कितना लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जो जल ग्रहण क्षेत्र से बाहर है?

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir, in the statement, which has been laid on the Table of the House, it has already been mentioned in detail. So, I would only like to repeat what has been mentioned here. The total catchment area in the country is...(Interruptions)...The annual average flow in the river systems of India is about 1869 BCM. (Interruptions)

SHRI SANTOSH BAGRODIA: You were telling about total catchment area. (Interruptions)

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: I am coming to that. I have this figure. Sir, I have a long list, river basin wise. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He wants total figure.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir, for total, I will have to calculate.

MR. CHAIRMAN: Calculate. It will take five minutes.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir, I can mention the accentuation. (Interruptions) No, Sir, I can mention the accentuation. (Interruptions) No, Sir, that is roughly about 37,000 sq. km. (Interruptions)

SHRI SANTOSH BAGRODIA: No, Sir, it is wrong. It is more than one lakh sq. kms.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो मेरे प्रश्न का जवाब दिया वह सही नहीं है। दो लाख से ज्यादा वर्ग किलोमीटर क्षेत्र केचमेंट एरिया से बाहर है।

दूसरा मेरा पूरक है कि करीब-करीब 162 मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स और 240 माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स पिछले 25-30 सालों से निर्माणाधीन हैं और इनमें से एक प्रतिशत भी इनके प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए हैं। इसके पूरा न होने के कारण उचित जल प्रबंधन नहीं होता और उचित जल प्रबंधन सरकार कर नहीं पा रही है। इसके परिणामस्वरूप, जहां सुखाड़ की स्थिति है, वहां जल नहीं पहुंचाया जा रहा है और दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जो आपकी लंबित परियोजनाएं हैं उनको आप किस समय सीमा के अंदर पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए क्या कार्य योजना आपने तैयार की है?

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Mr. Chairman, Sir, it is a fact that there are a large number of projects that have spilled over from one Five-Year Plan to another Five-Year Plan. In the Ninth Five-Year Plan, under the scheme, Accelerated Irrigation Benefits Scheme (AIBS), we are providing funds for the projects that have spilled over from one Five-Year Plan to another. Since 1996-97, it is being implemented; and, over the years, we have provided more than Rs. 5,000 crores to all the States so that the projects which have remained incomplete could be completed during the Ninth Five-Year Plan. You will kindly appreciate, Sir, that the implementation of the projects is in the hands of the State Government. No doubt, we provide funds, but the State Governments have to come forward to complete the project so that all the projects could be completed in a time-bound manner.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Chairman, Sir, I will restrict myself to Rajasthan because there is so much of scarcity of water in Rajasthan; there is so much of water available in the country, whereas Rajasthan is absolutely dry. If the surplus water is taken to Rajasthan, on the one hand, floods will not occur in those areas; and, on the other, it will be of help to Rajasthan. In the statement, it is said that Rajasthan has 60,000 sq. km. of catchment area; average annual flow is just negligible; completed projects — zero; projects under consideration — zero. Taking into account the "zero, zero" figures, I would like to know from the hon. Minister whether he has got any plan, whatsoever, to utilise the catchment area of 60,000 sq. km. which is available in Rajasthan.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: No doubt, Sir, Rajasthan is a water-deficit State in the country. Whatever projects were undertaken and financed by the Government there, especially the Indira Gandhi Canal Project, are under implementation. It is a fact that Rajasthan is a water-deficit State. To meet the water problem in Rajasthan, the National Water Development Agency (NWDA) was set up in 1982. This Agency is making studies as to where the water potential in different river basins could be found. Besides, we are thinking of providing water to Rajasthan by transferring water from the surplus basin to the deficit basin. If it is implemented, Rajasthan can be saved. Then, the State Government of Rajasthan have also sent a few projects to us. They are under consideration by the TAC of the CWC. Moreover, if the Indira Gandhi Canal Project which is under execution, is completed on time—because, as I said earlier, the execution and implementation of a project is in the hands of the State Government—then, if not 100% at least 50% of the water problem in Rajasthan would be solved.

[7 August, 2001]

RAJYA SABHA

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि हमारे यहां वार्षिक औसत नदी प्रवाह 1869 बिलियन घन मीटर है। इस समय जो भंडारण क्षमता है, वह केवल 177 बिलियन घन मीटर है। यह उसमें 75 की और बढ़ोत्तरी करने वाले हैं इस प्रकार से 252 बिलियन घन मीटर की भंडारण क्षमता होगी। भंडारण की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि बाढ़ से बचा जा सके और पानी जो समुद्र में चला जाता है, उसका सदुपयोग हो सके। मेरा "ए" पार्ट यह है कि 132 प्रस्ताव जो इनके पास इस समय विचाराधीन हैं, इन 132 प्रस्तावों पर कब तक अमल हो जाएगा ताकि जो हमारी भण्डारण की क्षमता है वह 384 बिलियन घन मीटर हो जाए? दूसरा श्रीमन, गंगा नदी का जो क्षेत्र है वह सबसे लम्बा क्षेत्र है-8,61,452 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र है। इसका जो प्रवाह है वह भी बहुत ज्यादा है, ब्रह्मपुत्र से थोड़ा सा कम है, बाकी और नदियों से सबसे ज्यादा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भण्डारण के अतिरिक्त नहर की प्रणालियों से भी उस व्यवस्था को प्राप्त किया जा सकता है जो बाढ़ से बचाए और हमारा पानी खराब भी न हो। गंगा नदी पर फिलहाल जो मध्य गंगा कैनल की एक परियोजना है जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसका दूसरा चरण जो बनना था वह दूसरा चरण मध्य गंगा का कब तक पूरा हो जाएगा।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir, the hon. Member has already stated that, over the years, we have created a live storage capacity of 177 BCM, i.e. billion cubic metre, in the country. This figure is up to the year 1995. And another 75 billion cubic metre of live storage will be created, if the on-going projects that are under implementation are completed, and another 132 BCM of live storage will be created. Sir, many projects are being considered for increasing the live storage capacity, they are at various stages of implementation at the present moment. Sir, about the Madhya Ganga Project, I have no specific information available with me right now. So, Sir, if you permit me, I can pass on the necessary information to the hon. Member.

श्री रमा शंकर कौशिक: यह प्रश्न तो इससे जुड़ा हुआ है।

श्री सभापति: उन्होंने कहा मेरे पास है नहीं, भिजवा देंगे।

श्री श्याम लाल: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूखे और बाढ़ से राहत के लिए क्या सम्पूर्ण भारत की बड़ी-बड़ी नदियों को आपस में इंटरलैंक करने के लिए कोई परियोजना है? यदि है तो किन-किन बड़ी नदियों को आपस में मिलाने की योजना है और यह कब तक पूरी होगी? दूसरा, यह है....

श्री सभापति: एक ही काफी है।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir, as I have already stated, it is a fact that in order to save the country both from the fury of floods as well as from the drought problem which occur in different parts of the country, we had set up the National Water Development Agency. This is a Society, and it is under the control of my Ministry, the Ministry of Water Resources. Over the years, this particular organisation has conducted various studies. Their pre-feasibility studies are already over. The main purpose of this organisation is to study the river basins. It is divided into two components, *i.e.* the peninsular component and the Himalayan component. The rivers which are flowing in the Himalayan region are called the "Himalayan component" and the rivers which are flowing, especially, in the Southern region, are called the "peninsular component". If we can connect these two river basins we can ferry the surplus water from the surplus basin to the deficit basin so that the problem of drought can be solved as well as the fury of floods can be minimised. This will certainly take time. Unfortunately, now, water has become a contentious issue between different States. And, unless the States, which are having surplus water, agree to share it with the deficit States, this programme cannot be implemented. However, the Government and my Ministry are trying their best to have a consensus among the States so that the water from the surplus region can be transported to the deficit region; and, in this process, both the problems of floods and drought can be solved and precious lives and property of the country can be saved.

MR. CHAIRMAN: This question is in connection with the rivers, not the answer that you have given.

श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता: मान्यवर, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वाटर मैनेजमेंट को आजादी के बाद लास्ट प्रायोरिटी दी गई है। किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, अरबों रुपये का नुकसान होता है और दूसरी जगह लोग प्यासे मरते हैं। मान्यवर, एनुअल फ्लो 1869 मिलियन क्यूबिक मीटर है और अभी तक जो कैचमेंट स्टोरेज फैसिलिटी की है यह 177 मिलियन क्यूबिक मीटर की गई है। That is up to 1995. That means we have done nothing during the last seven years. My first question to the hon. Minister is whether we have added any capacity during the last seven years or not.

सर, एनअदर रिलेटेड इश्यू इज कि बिहार में नेपाल से जो नदियां आती हैं, जैसे गंडक है, वे बिहार में हर बार, हर साल तबाही करती हैं, इसके लिए सरकार ने कुछ करने के लिए क्या कभी कोई सोचा है, क्या कभी कोई प्लान बनाई है, नेपाल सरकार के साथ क्या कोई इश्यू टेक अप किया है? वहां लाखों लोगों को हर साल नुकसान होता है, तबाही होती है और अरबों रुपयों का नुकसान होता है। क्या इसके लिए सरकार ने कुछ किया है?

[7 August, 2001]

RAJYA SABHA

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir, as I had stated earlier, 177 BCM live storage capacity was created. The hon. Member says that nothing has been done or no live storage capacity has been created during the last seven years. Capacity has been created, but there are some projects which are yet to be completed. As a result we cannot give the details of 75 BCM. But, certainly out of the 75 BCM...

SHRI PREM CHAND GUPTA: Why don't you provide those figures? You have stated that a storage capacity of 75 BCM is under construction. What capacity have you created during the last seven years? Why don't you provide that figure?

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: No doubt, some of the projects have been completed. I agree with the hon. Member that all projects have not been completed, but some have been completed.

So, far as the question regarding the rivers coming from Nepal is concerned, I may point out that we have been having discussions with the Government of Nepal. In these discussions, the Ministry of External Affairs is also involved. We are having official-level discussions with the Government of Nepal.

श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता: मान्यवर, इनको कितने साल चाहिए? पिछले 20 साल से ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी बात चल रही है। क्या इसका कभी कोई अंत होगा?... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: सर, पूरा बिहार नेपाल की नदियों के पानी से डूबा हुआ है, बाढ़ आ रही है।... (व्यवधान)...

श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता: पूरा नार्थ बिहार डूबा हुआ है। आप कितनी बार बात करेंगे?... (व्यवधान)...

प्रो. रामदेव भंडारी: सर, अगर बिहार को बाढ़ से मुक्त करना चाहते हैं तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी। अन्य कोई उपाय नहीं है।... (व्यवधान).... यह बात नहीं कर रहे हैं... (व्यवधान)...

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir, the issue is between two sovereign countries. The Government of India cannot do anything unilaterally, because it has international repercussions. However, over the years, we have been pursuing the matter and have been having discussions. Some of the issues we have resolved, but there are many issues which are yet to be resolved. We have been having a constant interaction with the Nepalese Government.

प्रो. रामदेव भंडारी: सर, एक हजार करोड़ से ज्यादा रुपया हर साल बिहार सरकार को बाढ़ पर खर्च करना पड़ता है।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: We are having regular discussions. As the hon. Member knows, the Mahakali Treaty has been signed between the Government of India and the Government of Nepal. Similarly, an agreement on Pancheshwar Dam has already been arrived at. To solve all these pending issues, it will certainly take time. Unless both the countries...*(Interruptions)*...

SHRI PREM CHAND GUPTA: How many years do you want to take?

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. Water is a real threat to the world, particularly, to India. My first question is related to the hon. Minister's written reply, line number 6 and lines number 12 and 13. For rain-harvesting, people of India are evolving indigenous methods. One such method has been evolved by Mr. Rajender Singh who has won the Magsasay award. Another person, Mr. Krishan Gupta from Allahabad has done it. He has suggested that catchment tanks could be constructed near the catchment rivers so as to release water during summer and to preserve drinking water. May I know from the Minister whether the Government is aware of these innovative programmes? I would also like to know whether his Ministry has done anything about it.

Part (b) of my question is whether the Government is planning to use satellite remote sensing to determine rainfall volumes, ecology and environment of the catchment rivers. And the final question which has already been raised is, what has been done about the Indo-Bhutan Joint River Commission to find a solution to the river waters dispute?

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Mr. Chairman, Sir, I will first answer the last question of the hon. Member. Regarding river water dispute between the two countries, as I have already stated, Bhutan is also a sovereign country. Therefore, the Ministry of Water Resources cannot discuss with them directly. We have to go through the Ministry of External Affairs. We are in constant touch with the Government of Bhutan. Recently, the Secretary of my Ministry has visited Bhutan and held discussions with his counterpart. We are very serious about it. The water released from the rivers of Bhutan and Nepal is inundating some of the areas of our States. As a result of this, our people and our States have suffered huge losses. Therefore, we are taking all possible steps to arrive at some kind of a solution, or, sign some kind of a treaty so that multipurpose projects can be constructed; and water coming from the rivers of these two countries can be regulated and utilised for the purpose of irrigation.

[7 August, 2001]

RAJYA SABHA

MR. CHAIRMAN: That is all right.

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Sir, the remaining two questions of mine have not been answered.

MR. CHAIRMAN: That is all right. You should have asked only one question, not three. Anyway, now Mr. Chavan.

SHRI S.B. CHAVAN: Mr. Chairman, Sir, looking at the population explosion and the condition of water scarcity in certain areas and the condition of floods in different areas, we would have to think in terms of bigger projects which can, in fact, connect surplus water areas with least water areas. As the hon. Minister said, there has been some kind of a preliminary study on this. Would he kindly enlighten the House as to how much surplus water has been found in the preliminary study which he has referred to; and whether the Government has any definite plan of action to implement the recommendations of this group?

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Mr. Chairman, Sir, the inter-linking of rivers between the Himalayan region and the Peninsular region will help us to irrigate an additional area of 25 million hectares.

SHRI NARENDRA MOHAN: How much extra water has been found in the perennial rivers of the Himalayan region?

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: We have extra water in the Himalayan region, especially, in the Ganga, the Brahmaputra and the Meghna basins. We have surplus water. We are thinking to connect these rivers with the Southern rivers, the Peninsular rivers so that the surplus water in the Himalayan rivers can be transported to the Deccan area. By this, we can irrigate 25 million hectares of land.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Airport infrastructure in the North-East

*223. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether any assessment has been made of the immediate airport infrastructure problems of the North-East Region;